



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

HO
11/4/88

सं० 480]
No. 480]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 1988/भाद्र 16, 1910
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1988/BHADRA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1988

आदेश

सा.का.नि. 909(अ) :--भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की समन्वय पर प्रयोजनोन्मुख अधिसूचना सं. सा.का.नि. 113(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1972 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आदेश सं. सा.का.नि. 553(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1975 को अधिस्तित करते हुए, सिवाए उन बातों के संबंध में जिनमें ऐसे अधिस्तित के पूर्व किया गया है या जो की जाने से छोड़ दी गई हैं, और कम्पनियों के उस वर्ग के संबंध में, जिसको यह आदेश लागू होता है, और अन्य आनुवंशिक विषयों की बाधत भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स संस्थान [को चार्टर्ड अकाउण्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अंतर्गत गठित किया गया है] से परामर्श करने के पश्चात्, कम्पनी विधि बोर्ड निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होता और प्रारम्भ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्माता और अन्य कम्पनी (निष्ठापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1988 है।

(2) (क) यह प्रत्येक ऐसी कम्पनी को, जिसके अस्तित्व कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 591 में

परिभाषित विदेशी कम्पनी भी है, जो निम्नलिखित विधायकताओं में से एक या अधिक में लगी हुई है या लगने की सम्भावना करनी है, लागू होगा, अर्थात् :-

(1) विनिर्माण, खनन या प्रसंस्करण;

(2) सेवाएं करना और उत्तका प्रवास करना;

(3) व्यापार; और

(4) वित्तपन, विनिधान, ब्रिट फंड, निधि या पारम्परिक अनुविधा गोसादियों का कारक।

(ख) यह निम्नलिखित की लागू नहीं होगा :-

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2(31) में परिभाषित बोर्ड कीमा कम्पनी, और

(iii) कोई भी कम्पनी, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत कार्य करने के लिए अनुज्ञाति दी गई है।

(3) यह 1 नवम्बर, 1988 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :

इस आदेश में,--

(क) "विद्य कंठ", "विधि" या "पारस्परिक प्रतुष्टि कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी ऐसे संसारदार या उद्धार के फोरम या समितियों के रूप में प्रत्यक्ष, संसार या पक्ष-वैधान के कारबार में लगी हुई है, जिसके द्वारा यह अनेक समितियों के साथ इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक किसी निश्चित अवधि के लिए किसी का किसी निश्चित राशि का अभिदाय करेगा तथा प्रत्येक अभिदाय, अपनी जारी पर, जो लिखित डाक कर या नौकाम द्वारा या विविध द्वारा या किसी अन्य ऐसी रीति में, जो कि कर में उल्लिखित की जाए, अवधारित की गई हो, प्राप्त करने का हक होगा, तथा उसके अन्तर्गत वे कम्पनियों आती हैं जिनका प्रधान कारबार अपने सदस्यों से निरन्तर निरन्तर स्वीकार करना और उन्हें धन उधार देना है ;

(ख) "विद्य कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग, वाणिज्य या कृषि के, उद्योग देकर या अभिदाय करके या अन्वया, विस्तीर्ण कारबार में लगी हुई है और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसी कम्पनी आती है, जो अब का पट्टा विन-पेयण और आवागम के विनियम के कारबार में लगी हुई है ;

(ग) "विनिर्माण कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जेवरों, स्काफों, बजावों, डिब्बेदारों, डिब्बेदार स्टाफों, जिनके अन्तर्गत प्रतिमूर्तियों भी हैं, अथवा ऐसी ही प्रकृति की अन्य विविध प्रतिमूर्तियों के अर्थ और आवागम के कारबार या उद्योग में लगी हुई है ;

(घ) "विनिर्माण कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में परिभाषित निम्न विनियमों में लगी हुई है :

(क) "खतम उद्योग" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी खान का स्वामी है, और उद्योग परीक्षा के अन्तर्गत प्रा. (ज) उद्योग पट्टेदार या अधिभोग के रूप में किसी खास क. कारबार करती है ;

(ख) "प्रसंस्करण कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो समग्र के प्रमाण, विक्रय, परिधान या व्यवस्था को छोड़ कर उनके प्रसंस्करण के कारबार में लगी हुई है ;

(ग) "सिवा कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो दूसरों के कारबार के लिए किसी सेवाओं, सुविधाओं, प्रतुष्टिओं करने और वेदों देना प्रदाय करने, उपबन्ध करने, उन्हें बनाए रखने और उनके व्यवस्था के कारबार में लगी हुई है ;

(घ) "आवागम कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो माल के आवागम और विक्रय के कारबार में लगी हुई है ।

3. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पैरा 4 और पैरा 5 में विनिर्दिष्ट विषय होंगे—लेखापरिषद द्वारा परीक्षित प्रतीत ऐसी कम्पनी के लेखाओं के बारे में, जिसको यह आदेश लागू है, इस आदेश के प्रावधान पर या उसके पश्चात् किसी दिन को समाप्त होने वाले प्रत्येक तिमाही वर्ष के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में वे विषय अन्विष्ट होंगे जो इस आदेश के पैरा 4 और पैरा 5 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय :

उक्त अधिनियम के, जिसको यह आदेश लागू है, लेखाओं के बारे में लेखापरिषद की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों के बारे में कथन सम्मिलित होगा, अर्थात्—

(क) विनिर्माण, खनन और प्रसंस्करण कम्पनी की दशा में,—

(1) क्या कम्पनी पूर्ण विनिर्माण दक्षित करने के लिए समुचित अभिलेख रख रही है, जिनके अन्तर्गत परिमाणानुसंगिक भारों और नियत आस्तियों की स्थिति भी है, क्या उन नियत आस्तियों की प्रबन्धक मंडल द्वारा युक्तियुक्त अन्तर्गतों पर अस्तित्व जांच कर ली गई है और यदि ऐसी जांच पर कोई तात्त्विक फर्म पाए गए हैं, और यदि ऐसा है तो क्या उनकी बाधा लेखा-वहियों में समुचित कार्यवाही कर ली गई है ;

(2) क्या नियत आस्तियों में से जिन्होंने का वर्ष के दौरान पुनर्निर्माण कर लिया है, यदि ऐसा है तो पुनर्निर्माण के आधार उपस्थित किया जाना चाहिए ;

(3) क्या प्रबन्ध मंडल ने तैयार माल, मंडारों, फालतू पुर्जों और कच्ची सामग्री के बारे में युक्तियुक्त अन्तर्गतों पर अस्तित्व जांच कर ली है ;

(4) क्या प्रबन्ध मंडल द्वारा स्टाफ की अस्तित्व जांच के लिए अनुमति की जाने वाली प्रक्रियाएं कम्पनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के संबंध में युक्तियुक्त और पर्याप्त हैं ? यदि नहीं तो ऐसी प्रक्रियाओं में अप्रतिष्ठताओं की रिपोर्ट की जानी चाहिए ;

(5) क्या पुस्तक अभिलेखों से तुलना की जाती है ऐसी अस्तित्व जांच पर, कोई तात्त्विक फर्म पाए गए हैं, तो क्या उनके बारे में लेखा-वहियों में समुचित कार्यवाही कर ली गई है ?

(6) क्या लेखा परीक्षक का स्टाफ की परीक्षा के आधार पर समाप्त हो गया है कि ऐसा मूल्यंकन सामान्यतः स्वीकृत लेखा विद्वानों के अनुसार उचित और उपयुक्त है ? क्या स्टाफ के मूल्यंकन का आधार सही है, जो पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया था ; यदि मूल्यंकन के आधार में कोई विचलन हुआ है तो ऐसे विचलन के प्रभाव के बारे में, यदि तात्त्विक हों तो रिपोर्ट की जानी चाहिए ;

(7) यदि कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्ट्रार में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों में और/या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 370 की उपधारा (1ख) के अधीन परिभाषित उसी प्रबन्ध मंडल के अधीन की कम्पनियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधार लिए हैं, तो क्या ऐसे ऋणों के ब्याज की दर और निवन्धन तथा शर्तें प्रथम दृष्टया कम्पनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ;

(8) यदि कम्पनी ने धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्ट्रारों में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को और/या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 370 की उपधारा (1ख) के अधीन परिभाषित उसी प्रबन्ध मंडल के अधीन की कम्पनियों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधार दिए हैं तो क्या ऐसे ऋणों के ब्याज की दर और निवन्धन और शर्तें प्रथम दृष्टया कम्पनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ;

(9) क्या वे पक्षकार, जिन्होंने कम्पनी द्वारा उधार या उधारों की प्रकृति के अभिदाय दिए गए हैं, मूल्यंकन की रकमों

का क्या अनुबन्धित रूप में प्रतिस्वाय कर रहे हैं और व्याज का संवाय भी नियमित रूप से कर रहे हैं, और यदि नहीं, तो क्या कम्पनी ने मूलधन और व्याज की बसुली के लिए युक्तियुक्त उपाय किए हैं ;

- (10) क्या भंडारों, कच्ची सामग्री, जिसके अन्तर्गत संयंत्रक, संयंत्र और मशीनरी उपकरण तथा अन्य आस्तियां भी हैं, के क्रय के लिए और माल के विक्रय के लिए कम्पनी के आकार और उसके कारखानों की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है ;
- (11) क्या माल और सामग्रियों के क्रय तथा माल, मन्त्रियों और सेवाओं के विक्रय के व्यवहार, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर(रों) में प्रविष्ट की गई संविदाओं या ठहरावों के अनुसरण में किए गए हैं और जो प्रत्येक पक्षकार के बारे में वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) या उससे अधिक है, उन कीमतों पर किए गए हैं जो ऐसे माल, सामग्रियों, या सेवाएं के लिए विद्यमान बाजार मूल्य को या उन कीमतों पर, जिन पर उसी प्रकार के माल या सेवाओं के लिए व्यवहार अन्य पक्षकारों के साथ किए गए हैं, हानि में रखते हुए, युक्तियुक्त है ;
- (12) क्या किन्हीं अनुपयोगी या अतिरिक्त भंडारों, कच्ची सामग्री या तैयार माल का अवधारण किया गया है और क्या हानि के लिए, यदि कोई हो, कोई उपयुक्त लेखाओं में किया गया है ;
- (13) यदि कम्पनी ने जहां से विशेष स्वीकार किए हैं तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-क के उपबन्धों और उसके अधीन विरचित नियमों का, जहां वे लागू हों, अनुपालन किया गया है, यदि नहीं, तो उल्लंघनों की प्रकृति का कथन करें ;
- (14) क्या कम्पनी आपत्तीय उपोत्पादों और स्कोरों के विक्रय और व्ययन के लिए, जहां लागू हों, युक्तियुक्त अभिवेक्ष रख रही है ;
- (15) उन कम्पनियों के संघ में, जिनकी संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में नवावत पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक है, या संबंधित वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए औसत वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक है, क्या कम्पनी को उसके आकार और उसके कारखानों की प्रकृति के अनुरूप कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति है ;
- (16) जहां केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 (1) (ब) के अधीन लागत अभिलेख का रखा जाना विहित किया है, वहां क्या ऐसे लेखा और अभिलेख रखाए गए हैं ;
- (17) क्या कम्पनी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा शोध्यों का समुचित प्राधिकारी के पास निवेश नियमित रूप से कर रही है, और यदि नहीं, तो भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा शोध्यों की बकाया की मात्रा लेखापरीक्षक द्वारा उपदर्शित की जाएगी ;
- (18) क्या आय-कर, घन कर, निशुल्क कर, सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत संवेग धोई विविध रकमों

जो उस तारीख से, जिससे वे संवेग धोई, छह मास से अधिक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को बकाया थीं, यदि ऐसा है तो ऐसे बकाया शोध राशियों की रिपोर्ट की जानी चाहिए ;

- (19) क्या वैयक्तिक व्यय राजस्व लेखा पर आरित किए गए हैं ; यदि ऐसा है तो उसके बारे में की रिपोर्ट की जानी चाहिए ;
- (20) क्या कम्पनी रजग औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 3 का उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधिनियत रजग औद्योगिक कम्पनी है ; यदि ऐसा है तो क्या उस अधिनियम की धारा 15 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय सुपरिवीज बोर्ड की कोई निर्देश प्राप्त हुआ है ।

(ख) सेवा कम्पनी की दशा में,—

- (1) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सभी विषय, उस विस्तार तक जहां तक वे लागू हैं ;
- (2) क्या कम्पनी के पास नामधियों और भंडारों की प्राप्ति, निर्माण और जानी-अमानि विनिर्दिष्ट करने की, और संबंधित कार्यों में जांचों की गई सामग्रियों को आवंटित करने की उसके आकार और उसके कारखानों की प्रकृति के अनुरूप, युक्तियुक्त पद्धति है ;
- (3) क्या कम्पनी के पास उसके आकार और उनके कारखानों की प्रकृति के अनुरूप संबंधित कार्यों में लगाए गए अन्य घंटों के आवंटन की कोई सुव्यवस्था पद्धति है ;
- (4) क्या भंडारों के जारी किए जाने और कार्यों के लिए भंडारों और अन्य के आवंटन पर समुचित स्तरों पर प्राधिकरण की सुव्यवस्था पद्धति और कम्पनी के आकार और उसके कारखानों की प्रकृति के अनुरूप कोई आन्तरिक नियंत्रण की पद्धति विद्यमान है ।

(ग) व्यापारी कम्पनी की दशा में,—

- (1) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सभी विषय, उस विस्तार तक जहां तक वे लागू हैं ;
- (2) क्या अनियमित माल का अवधारण किया गया है और यदि ऐसे माल का मूल्य महत्वपूर्ण है तो क्या हानि के लिए उपयुक्त किया गया है ;

(घ) वित्त, विनिर्माण, चिट फंड, निधि और पारस्परिक प्रभुविधा कम्पनी की दशा में,—

- (1) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सभी विषय, उस विस्तार तक जहां तक वे लागू हैं ;
- (2) क्या उस मामले में, जिसमें कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरकी के रूप में प्रतिभूति के आधार पर उधार और अधिदान किए हैं, पर्याप्त इस्तमोज और अभिलेख रखे गए हैं ;
- (3) क्या चिट फंड, निधि या पारस्परिक प्रभुविधा सोसाइटी को लागू किसी विशेष कानून के उपबन्धों का सम्पूर्ण अनुपालन किया गया है ;
- (4) यदि कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य वित्तियों का लेन देन या व्यापार करती है तो क्या

संयोजकों और संविदाओं के समुचित अभिलेख रखे गए हैं और क्या उसमें समय पर प्रविष्टियाँ की गई हैं, और क्या कम्पनी ने शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेन्चर और अन्य विनिमय करने की बात में, उस छूट के, यदि कोई हो, विस्तार तक के सिवाय धारण किए हैं, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 49 के अधीन दी गई है।

5. अनुसूच या विशेषित उत्तरों के लिए कारणों का कथन किया जाएगा:—जहाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, पैरा 4 में निर्दिष्ट प्रश्नों में से किसी का उत्तर अनुसूच या विशेषित है, वहाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, यथास्थिति, ऐसे अनुसूच या विशेषित उत्तर के लिए कारणों का कथन भी किया जाएगा। जहाँ लेखापरीक्षक किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है, वहाँ उसकी रिपोर्ट में यह तथ्य इस बात के कारणों सहित उल्लिखित किया जाएगा कि उसके लिए ऐसे प्रश्न का उत्तर देना क्यों सम्भव नहीं है।

[फाइल सं. 12/5/86—सो. एल. 5]
एस. कुमार सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th September, 1988

ORDER

G.S.R. 909 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Notification of the Government of India in the Department of Company Affairs, No. GSR 443 (E) dated the 18th October, 1972 as amended from time to time and in supersession of the order No. GSR 553 (E) dated the 7th November, 1975 except as regards things done or omitted to be done before such supersession, and after consultation with the Institute of Chartered Accountant of India (constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)), in regard to class of companies to which this order applies and other ancillary matters, the Company Law Board hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title application and commencement.—

(1) This Order may be called the Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Order, 1988.

(2) (a) It shall apply to every company including a foreign company as defined in Section 5(91) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which is engaged or proposes to engaged in one or more of the following activities namely:—

- (i) Manufacturing, mining or processing;
 - (ii) supplying and rendering services;
 - (iii) trading; and
 - (iv) the business of financing, investment, chit fund, nidhi or mutual benefit societies.
- (b) It shall not apply to

- (i) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
- (ii) an insurance company as defined in section 2(21) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and
- (iii) a company licensed to operate under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(3) It shall come into force on the 1st day of November, 1988.

2. Definitions :

In this Order:—

- (a) "Chit fund", "nidhi" or "mutual benefit" company means a company engaged in the business of managing, conducting or supervising as a foreman or agent of any transaction or arrangement by which it enters into an agreement with a number of subscribers that every one of them shall subscribe a certain sum of instalments for a definite period and that each subscriber, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be provided for in the agreement, shall be entitled to a prize amount, and includes companies whose principal business is accepting fixed deposits from, and lending money to, members;
- (b) "finance company" means a company engaged in the business of financing, whether by making loans or advances or otherwise, of any industry, commerce or agriculture and includes any company engaged in the business of hire-purchase, lease financing and financing of housing;
- (c) "investment company" means a company engaged in the business of acquisition and holding of, or dealing in, shares, stocks, bonds, debentures, debenture stocks, including securities issued by the Central or any State Government or by any local authority, or in other marketable securities of a like nature;
- (d) "manufacturing company" means a company engaged in any manufacturing process as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (e) "mining company" means a company owning a mine, and includes a company which carries on the business of a mine either as a lessee or occupier thereof;
- (f) "processing company" means a company engaged in the business of processing materials with a view of their use, sale, delivery or disposal;
- (g) "Service company" means a company engaged in the business of supplying, providing, maintaining and operating any services.

facilities, conveniences, bureaux and the like for the benefit of others;

- (h) "trading company" means a company engaged in the business of buying and selling goods.

3. Auditor's report to contain matters specified in paragraphs 4 and 5 :

Every report made by the auditor under section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on the accounts of every company examined by him to which this Order applies for every financial year ending on any day on or after the commencement of this Order, shall contain the matters specified in paragraphs 4 and 5.

4. The matters to be included in the Auditor's Report :

The Auditor's Report on the accounts of a company to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely :—

(A) In the case of manufacturing, mining or processing company :—

- (i) Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets; whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;
- (ii) whether any of the fixed assets have been revalued during the year; if so, the basis of revaluation should be indicated;
- (iii) whether physical verification has been conducted by the management at reasonable intervals in respect of finished goods, stores, spare parts and raw materials;
- (iv) Are the procedures of physical verification of stocks followed by the management reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business? If not, the inadequacies in such procedures should be reported;
- (v) whether any material discrepancies have been noticed on physical verification of stocks as compared to book records, and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account?
- (vi) whether the auditor, on the basis of his examination of stocks, is satisfied that such valuation is fair and proper in accordance with the normally accepted accounting principles? Is the basis of valuation of stocks same as in the preceding year?, if there is any deviation in the basis of valuation, the effect of such deviation, if material, should be reported;

(vii) if the company has taken any loans, secured or unsecured, from companies, firms or other parties listed in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and/or from the companies under the same management as defined under sub-section (1B) of section 370 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), whether, the rate of interest and other terms and conditions of such loans are prima facie prejudicial to the interest of the company;

(viii) if the company has granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties listed in the register (s) maintained under section 301 and/or to the companies under the same management as defined under sub-section (1B) of section 370 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), whether the rate of interest and other terms and conditions of such loans are prima facie prejudicial to the interest of the company;

(ix) whether the parties to whom the loans, or advances in the nature of loans, have been given by the company are repaying the principal amounts as stipulated and are also regular in payment of the interest and if not whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;

(x) is there an adequate internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of stores, raw materials, including components, plant and machinery, equipment and other assets, and for the sale of goods;

(xi) whether the transaction of purchase of goods and materials and sale of goods, materials and services, made in pursuance of contracts or arrangements entered in the register(s) maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) as aggregating during the year to Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand) or more in respect of each party, have been made at price which are reasonable having regard to prevailing market prices for such goods, materials, or services or the prices at which transactions for similar goods or services have been made with other parties;

(xii) whether any unserviceable or damaged stores, raw materials, or finished goods, are determined and whether provisions for the loss, if any, have been made in the accounts;

(xiii) in case the company has accepted deposits from the public, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of section 58A of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder, where applicable, have been complied with. If not, the nature of contraventions should be stated;

- (xiv) is the company maintaining reasonable records for the sale and disposal of realisable by-products and scraps, where applicable;
- (xv) in the case of companies having a paid-up capital exceeding Rs. 25 lakh as at the commencement of the financial year concerned, or having an average annual turnover exceeding Rs. 2 crores for a period of three consecutive financial years immediately preceding the financial year concerned, whether the company has an internal audit system commensurate with its size and nature of its business;
- (xvi) where maintenance of cost records has been prescribed by the Central Government under section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), whether such accounts and records have been made and maintained;
- (xvii) is the company regular in depositing Provident fund and Employees' State Insurance dues with the appropriate authority and if not, the extent of arrears of Provident Fund and Employees' State Insurance dues shall be indicated by the auditor;
- (xviii) whether any undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, customs duty and excise duty were outstanding, as at the last day of the financial year concerned, for a period of more than six months from the date they became payable; if so, the amounts of such outstanding dues should be reported;
- (xix) whether personal expenses have been charged to revenue account; if so, the details thereof should be reported;
- (xx) whether the company is a sick industrial company within the meaning of clause (o) of sub-section (1) of section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986); if so, whether a reference has been made to the Board for Industrial and Financial Reconstruction under section 15 of that Act;
- (B) In the case of a service company :
- (i) all the matters specified in clause (A) to the extent to which they are applicable;
- (ii) whether the company has a reasonable system of recording receipts, issues and consumption of material and stores and allocating materials consumed to the relative jobs, commensurate with its size and nature of its business;
- (iii) whether the company has a reasonable system of allocating manhours utilised to the relative jobs, commensurate with its size and nature of its business;
- (iv) whether there is a reasonable system of authorisation at proper levels, and an adequate system of internal control commensurate with the size of the company and the nature of its business, on issue of stores and allocation of stores and labour to jobs.
- (C) In the case of a trading company :
- (i) all the matters specified in clause (A) to the extent to which they are applicable;
- (ii) have the damaged goods been determined and if the value of such goods is significant, has provision been made for the loss;
- (D) In the case of a finance, investment, chit fund, nidhi or mutual benefit company :
- (i) all the matters specified in clause (A) to the extent to which they are applicable;
- (ii) whether adequate documents and records are maintained in a case where the company has granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities;
- (iii) whether the provisions of any special statute applicable to chit fund, nidhi or mutual benefit society have been duly complied with; and
- (iv) if the company is dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments, whether proper records have been maintained of the transactions and contracts and whether timely entries have been made therein; also whether the shares, securities, debentures and other investments, have been held by the company in its own name except to the extent of the exemption, if any, granted under section 49 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
5. Reason to be stated for unfavourable or qualified answers :
- Where, in the Auditor's Report, the answer to any of the questions referred to in paragraph 4 is unfavourable or qualified, the Auditor's Report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified answer, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion in answer to a particular question, his report shall indicate such fact together with the reasons why it is not possible for him to give an answer to such question.

[File No. 12/5/86-CL-V]

S. KUMAR, Member Company Law Board.